साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 08-14 मार्च 2024 वर्ष-9, अंक-51

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

किसान हो रहे आत्मनिर्भरः अभी देश में गेहूं की दूसरी सबसे बड़ी खरीद राजस्थान में हुई

बिचौलियों की दुकान बंद

गेहूं बेचने के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन प्रदेश में हुआ

मध्यप्रदेश-राजस्थान में 125 रुपए दिया जा रहा बोनस

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में एमपी ने पंजाब को पछाड़ा

भोपाल। जागत गांव हमार

रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की खरीद देश के सभी प्रमुख उत्पादक सूबों में शुरू हो गई है। पांच अप्रैल तक पांच लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 4,81,080 मीट्रिक टन की खरीद मध्य प्रदेश में हुई है। आमतौर पर गेहूं खरीद में नंबर वन रहने वाले पंजाब में सबसे तेजी से खरीदी होती है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश आगे चल रहा है। वजह यह है कि मध्य प्रदेश में खरीद पहले से हो रही है, जबकि पंजाब में एक अप्रैल को खरीद शुरू होने के बावजूद अब तक मंडियां सूनी पड़ी हैं।

हालांकि, पिछले साल पंजाब ने देश में सबसे अधिक 1,21,16,774 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था। मध्य प्रदेश में गेहूं की बिक्री पर किसानों को एमएसपी के ऊपर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस मिल रहा है। जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है। पिछले साल मध्य प्रदेश एमएसपी पर सेंट्रल पूल में गेहूं बेचने वाला पंजाब के बाद दूसरा प्रमुख राज्य था। हालांकि अपना खरीद लक्ष्य नहीं हासिल कर पाया था। साल 2023 में मध्य प्रदेश को 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य दिया गया था, जबकि यहां पर 71 लाख मीट्रिक टन की ही खरीद हो पाई थी। हालांकि, इस बार यह खरीद में सबसे आगे है।

श्योपुर मंडी में गेहूं की बंपर आवक

तीन दिन में 52 हजार क्विंटल बिका

श्योपुर। कृषि उपज मंडी श्योपुर के साथ ही अंचल की मंडियां इन दिनों गेहूं से गुलजार बनी हुई हैं। मंडी प्रांगण में इन दिनों गेहूं से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतार और गेहूं के ढेर ही दिखाई दे रहे हैं। मंडी में इन दिनों हो रही गेहूं की बंपर आवक का आंकलन इससे किया जा सकता है कि पिछले तीन दिन में मंडी में 52 हजार क्विंटल गेहूं खरीदा गया है। जबकि 300 करीब ट्रॉलियां मंडी में अभी भी बिकने से शेष होकर कतारबद्ध हैं। यह स्थिति तो शहर की मंडी की है, जबकि श्योपुर के साथ ही बड़ौदा, कराहल और विजयपुर मंडी में भी प्रति दिन खासा गेहूं पहुंच रहा है।

गेहूं खरीद में दूसरे नंबर पर राजस्थान

अभी तक देश में गेहूं की दूसरी सबसे बड़ी खरीद राजस्थान में हुई है। यहां भी सरकार मध्य प्रदेश की तरह गेहूं की तय एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल पर 125 रुपए का बोनस दे रही है। यानी किसानों को गेहूं का दाम 2400 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। पांच अप्रैल तक यहां पर 12,446 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका था। जबकि उत्तर प्रदेश में अब तक सिर्फ 7,209.21 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। पिछले साल भी उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद के मामले में अपने लक्ष्य से काफी पीछे था। हरियाणा और पंजाब जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में हुई खरीद का अब तक कोई आंकड़ा नहीं आया है। दोनों राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद काफी सुस्त है।

एमएसपी का अब तक भुगतान

गेहूं खरीद प्रक्रिया जारी रहने के बीच अब तक 31 करोड़ 56 लाख रुपए का एमएसपी के तौर पर भुगतान हुआ है। जिसमें से 17 करोड़ 95 लाख मध्य प्रदेश के किसानों को मिले हैं, जबकि 11 करोड़ 84 लाख रुपए राजस्थान और पौने दो करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला है। सरकार अब आढ़तियों को किनारे हटाकर सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में एमएसपी का भुगतान कर रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के वक्त किसानों के बैंक अकाउंट नंबर भी लिए गए हैं। अब तक देश के 1,816 किसानों को गेहूं बिक्री के बाद पैसा मिल चुका है।

रिकॉर्ड किसानों ने करवाया रजिस्ट्रेशन

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक 19,54,970 किसानों ने एमएसपी पर सरकार को गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। यह रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 में गेहूं की एमएसपी का फायदा उठाने वाले किसानों की संख्या से कम है। पिछले वर्ष 21,28,159 किसानों सरकार को गेहूं बेचा था। फिलहाल, रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 सबसे ज्यादा 15,35,016 किसानों ने मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा 2,61,083 किसानों ने उत्तर प्रदेश और 91,059 ने राजस्थान में गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभी तक हरियाणा के 32,214, बिहार के 13,273 और पंजाब के 11,344 किसानों के रजिस्ट्रेशन की सूचना है।

दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर बोनस देगी राज्य सरकार

» मंडला में सीएम डॉ. मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंडला में कहा कि अब गंभीर बीमार व्यक्ति को जिले के कलेक्टर के अनुमोदन पर एयर एंबुलेंस सेवा का लाभ आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क मिलेगा। वहीं केंद्र की पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय, जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल के साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ केंद्र की मोदी सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि जो किसान पशुपालन करते हैं और जो नहीं करते हैं,वे भी पशुपालन करें उनके लिए योजना लाएंगे। जो दूध उत्पादन करते हैं, उन्हें हम प्रति लीटर बोनस आने वाले समय मे देंगे। कोदो-कुटकी में भी हम बोनस देंगे। बहनों के लिए एक और योजना लेकर आएंगे,सिलाई के कारखाने डालेंगे। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो मंडला में भी गारमेंट्स फैक्ट्री डलेगी। मंडला जिले को मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिली है। साथ ही अब मंडला संसदीय क्षेत्र में आयुर्वेद कॉलेज की भी सुविधा मिलेगी।

उम्मीदः लोकसभा चुनाव के बाद खाते में आएगा पैसा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया वादा

अब मध्य प्रदेश में किसानों को मिलेगा धान का भी बोनस

भोपाल। जागत गांव हमार

अभी 100 दिन ही हमारी सरकार को हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में जहां-जहां जनता की जो मांग थी वहां विकास के नए-नए कार्य शुरू किए गए हैं। शहडोल में जल्दी ही आयुर्वेदिक कॉलेज बनेगा। पटवारी नामांतरण करके किसानों के घर पहुंचेंगे यह हमारी सरकार का निर्णय हुआ है। यह बात मप्र के सीएम डॉ. मोहन यादव में शहडोल प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में मंच से कही। सीएम ने कहा कि पीएम श्री हेलीकॉप्टर एंबुलेंस की सुविधा देने का काम किया है। युवाओं के सारे दस्तावेज अब डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिंता मत करना धान का भी बोनस किसानों को दिया जाएगा। यह हमारी सरकार का निर्णय है। गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले गेहूं पर भी 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा कर चुकी है। सरकार की इस घोषणा से किसानों के मायूस चहरे खिल गए हैं। हालांकि किसानों को धान पर मिलने वाले बोनस के लिए अभी कम से कम बजट तक इंतजार करना होगा, क्योंकि राज्य सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि वह फिलहाल धान पर किसानों को बोनस दे सके, लेकिन 3100 प्रति क्विंटल की धान खरीदने की बात भाजपा ने चुनाव के पहले कही थी। मोदी गारंटी के चलते किसानों को इस बात की उम्मीद है कि राज्य सरकार उन्हें 3100 के पैसे जरूर देगी।

8 लाख किसानों को इंतजार

साल 2022 और 23 में मध्य प्रदेश में लगभग 46 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस साल भी मध्य प्रदेश में इसी लक्ष्य के साथ धान की खरीदी की गई है। इस साल लगभग 8 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था।

3100 क्विंटल खरीदने का था वादा

भाजपा ने अपनी घोषणा पत्र में कहा था कि धान पर समर्थन मूल्य के अलावा 900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया जाएगा, लेकिन अब जबकि धान खरीदी हो चुकी है। लेकिन किसानों को फिलहाल मात्र 2183 रुपए ही समर्थन मूल्य के हिसाब से मोटे धान का भुगतान किया गया है। किसानों को उम्मीद थी कि इसी के साथ उन्हें 900 रुपए क्विंटल के हिसाब से बोनस भी मिल जाएगा, लेकिन बोनस नहीं मिला है।

400 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा

मध्य प्रदेश में वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए हो सकता है कि किसानों को बोनस के लिए बजट के बाद तक इंतजार करना पड़े, क्योंकि लगभग 46 लाख टन धान खरीदने के बाद यदि 900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार किसानों को बोनस देगी, तो राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

उत्पादन को लेकर मौसम विभाग ने दी जानकारी

मप्र छोड़कर गेहूं उत्पादक राज्यों को चेतावनी नहीं

देश में बढ़ती गर्मी से नहीं घटेगी गेहूं की पैदावार

भोपाल। जागत गांव हमार

इस बार गर्मियों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस साल अप्रैल से जून के बीच अत्यधिक गर्मी महसूस की जाएगी। इसका सबसे अधिक असर मध्य और पश्चिमी भारत में दिखेगा। मौसम विभाग ने यह जानकारी तब है जब अप्रैल से जून के बीच देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। यानी वोटर्स को राजनीतिक गर्मी के साथ मौसमी गर्मी का भी अहसास करना पड़ेगा। आईएमडी ने सोमवार को कहा कि तापमान में वृद्धि का गेहूं की तैयार फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत में अप्रैल-जून की अवधि के दौरान अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम कार्यालय ने कहा कि गेहूं की कटाई के दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों और पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर और देश के बाकी हिस्सों में सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। हालांकि, आईएमडी प्रमुख ने कहा कि मध्य प्रदेश को छोड़कर गेहूं उत्पादक राज्यों के लिए लू की कोई चेतावनी नहीं है।

क्या कहा मौसम विभाग ने

भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अप्रैल-जून की अवधि के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, मध्य और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत में इसकी उच्च संभावना है। इसी क्रम में आईएमडी ने एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश को छोड़कर गेहूं उत्पादक राज्यों में 10 अप्रैल तक लू की कोई चेतावनी नहीं है। इससे साफ है कि गर्मी का असर इस बार गेहूं की फसल पर नहीं दिखेगा, इसलिए गेहूं की पैदावार गिरने की आशंका न के बराबर है।

आएंगे दो पश्चिमी विक्षोभ

महापात्र ने कहा कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। इस अवधि के दौरान मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्म हवा चलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्यतः चार से आठ दिनों की तुलना में दस से 20 दिनों तक लू चलने की आशंका है।

महापात्र ने कहा कि मध्य प्रदेश में इस समय तापमान 37-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अगले सप्ताह 42 डिग्री तक जाने की संभावना है। चूंकि राज्य में गेहूं की कटाई का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने 2022-23 के दौरान 110.55 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया। इसमें से उत्तर प्रदेश का हिस्सा 30.40 प्रतिशत, मध्य प्रदेश का 20.56 प्रतिशत, पंजाब का 15.18 प्रतिशत, हरियाणा का 9.89 प्रतिशत और राजस्थान का 9.62 प्रतिशत था।

इस तरह रहेगा मौसम

गर्मी की लहरों के शुरुआती हमले ने 2022 में भारत में गेहूं की फसल को प्रभावित किया, उत्पादन 2021 में 109.59 मिलियन टन से घटकर 107.7 मिलियन टन हो गया। इसने देश, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत को निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर दिया। गेहूं की फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अधिकांश हिस्सों में कटाई अप्रैल के आसपास शुरू होती है। आईएमडी ने बताया कि 80-85 प्रतिशत गेहूं की फसल या तो जल्दी या समय पर 25 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच बोई गई थी, जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक बोए गए क्षेत्र में गर्मी सहने वाली किस्मों को लगाया गया था। इस साल गेहूं का उत्पादन करीब 112-114 मिलियन टन होने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश का गेहूं उत्पादन 2017-18 में 99.87 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में 110.55 मिलियन टन हो गया। इस अवधि के दौरान गेहूं की खेती का क्षेत्रफल 29.67 हेक्टेयर से बढ़कर 31.78 मिलियन हेक्टेयर हो गया। मौसम कार्यालय ने कहा कि अप्रैल में मध्य भारत के कई इलाकों और उत्तरी मैदानी इलाकों और दक्षिण भारत के आसपास के इलाकों में सामान्य से अधिक गर्मी वाले दिन रहने की संभावना है।

लू चलने की आशंका

महापात्र के अनुसार, इन क्षेत्रों में सामान्यत: एक से तीन दिनों की तुलना में दो से आठ दिनों तक लू चलने की आशंका है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अप्रैल में गर्मी का सबसे बुरा असर होने का अनुमान है। भारत में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच सात चरणों में होंगे।

मांग से अधिक गेहूं का उत्पादन, एक्सपोर्ट बैन

देश में एमएसपी से ज्यादा खुले बाजार में गेहूं का दाम

भोपाल। जागत गांव हमार

उपभोक्ता मामले विभाग के प्राइस मानिटरिंग डिवीजन के अनुसार 31 मार्च को देश में गेहूं का औसत दाम 30.86 रुपए प्रति किलो था। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम प्लेटफार्म पर भी यही पता चल रहा है कि देश की कई मंडियों में गेहूं का दाम एमएसपी से ज्यादा है। रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। गेहूं के दाम का यह हाल तब है जब महंगाई कम करने के नाम पर 8 फरवरी तक सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत सिर्फ 2150 रुपए प्रति क्विंटल के रियायती दर पर 80.04 लाख मीट्रिक टन गेहूं निजी और सहकारी क्षेत्र को बेच चुकी है। यही नहीं मांग से ज्यादा गेहूं उत्पादन का भी अनुमान है और एक्सपोर्ट भी बंद है. ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद गेहूं की महंगाई को बढ़ा कौन रहा है। सवाल यह है कि क्या व्यापारी, बड़े चेन रिटेलर और गेहूं के प्रोसेसर इसे स्टॉक कर रहे हैं। गेहूं को आसमान निगल गया या यह जमीन में समा गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नई फसल आने के बावजूद गेहूं महंगा है। इस बीच सरकार ने महंगाई पर काबू रखने के लिए गेहूं कारोबारियों को स्टॉक की घोषणा करने के काम को एक अप्रैल से आगे भी जारी रखने को कहा है। इसका मतलब अपने आप में साफ है कि गड़बड़ी कहां से हो रही है। किसानों के हाथ से जैसे ही गेहूं व्यापारियों के हाथ में पहुंचता है उसका दाम आसमान पर पहुंच जाता है।

मांग से ज्यादा उत्पादन

किसी भी फसल का दाम बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण होता है। यह कारण है डिमांड और सप्लाई का। अगर मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम है तो सामान महंगा होगा। गेहूं की महंगाई 2021 के बाद कायम है। जबकि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में संसद को बताया है कि 2021-22 में मांग 971.20 लाख टन थी। जबकि तब उत्पादन 1077.42 लाख टन था। बताया गया है कि इस समय देश में गेहूं की खपत लगभग 1050 लाख टन सालाना है, जबकि उत्पादन इससे करीब 70 लाख टन अधिक है।

उत्पादन पर एक नजर

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2023-24 में गेहूं का उत्पादन 1120.19 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 1105.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख मीट्रिक टन अधिक है। गेहूं का उत्पादन खपत की तुलना में 70 लाख टन ज्यादा है। गेहूं का एक्सपोर्ट भी 13 मई 2022 से पूरी तरह से बंद है। किसान एक्सपोर्ट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने अब तक इसे बैन ही रखा हुआ है।

सरकार के सामने समस्या क्या है

पिछले दो सीजन से सरकार अपना खरीद लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है। रबी सीजन 2023-24 में 341.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि खरीद सिर्फ 2.62 लाख मीट्रिक टन की ही हो पाई थी। इसी तरह रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में भी गेहूं की खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। तब 444 लाख मीट्रिक टन की जगह सिर्फ 187.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की ही खरीद हो पाई थी। वजह यह है कि बाजार में दाम एमएसपी से ज्यादा था। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए पहले से बहुत कम सिर्फ 320 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का ही लक्ष्य रखा है। अगर इस समय बाजार में दाम एमएसपी से ज्यादा रहता है तो फिर इस साल भी ऐसा संभव है कि यह लक्ष्य हासिल न हो पाए। ऐसा होगा तो सरकार कैसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देगी। बफर स्टॉक के लिए पर्याप्त खरीद जरूरी है।

देश में पंजाब का सबसे ज्यादा योगदान, पिछले साल की तुलना में कम हुई खरीद

चावल खरीद लक्ष्य के नजदीक पहुंची सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

भारतीय खाद्य निगम ने मार्च तक 45.44 मिलियन टन (एमटी) चावल की खरीद पूरी कर ली है। खरीफ मार्केटिंग सीजन-2023-24 के तहत चावल की खरीद एक अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी। यह एक साल पहले की खरीद 49.01 मिलियन टन से 7.3 प्रतिशत कम है। हालांकि, छत्तीसगढ़ में चावल की खरीद, जो 4 फरवरी को समाप्त हुई। पिछले साल 5.87 मिलियन टन के मुकाबले 8.3 मिलियन टन थी। यह 7.82 मिलियन टन के उत्पादन अनुमान से अधिक है, जो संपूर्ण खरीद तंत्र पर सवाल उठाता है। खरीफ में उगाए जाने वाले चावल की खरीद का लक्ष्य 52.5 मिलियन टन है। झारखंड में 30 अप्रैल तक, पश्चिम बंगाल में 31 मई तक और असम में 30 जून तक खरीद जारी रहेगी। खरीद का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार को 4-5 मिलियन टन और चावल खरीदने की उम्मीद है। अगर पश्चिम बंगाल में खरीद में तेजी आती है तो यह संभव है। पश्चिम बंगाल चावल का अग्रणी उत्पादक है। यहां एक साल पहले के 2.07 मिलियन टन की खरीद में 0.78 मिलियन टन की गिरावट दर्ज की गई है।

पंजाब, हरियाणा और अन्य उत्तरी राज्यों में चावल की खरीद दिसंबर 2023 में पूरी हो गई थी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह 31 जनवरी को और पूर्वी यूपी में 29 फरवरी 2024 को समाप्त हुई। एफसीआई ने पंजाब में 12.41 मिलियन टन की खरीद की है, जो एक साल पहले के 12.19 मिलियन टन से 2 प्रतिशत अधिक है और हरियाणा में यह 2022-23 में 3.95 मिलियन टन के मुकाबले 3.94 मिलियन टन है।

तेलंगाना में अब तक हुई खरीद

उत्तर प्रदेश में, केंद्र ने एक साल पहले के 4.39 मिलियन टन के मुकाबले 3.61 मिलियन टन चावल खरीदा है। तेलंगाना में चावल की खरीद 4.36 टन के मुकाबले 3.17 मिलियन टन रही है। ओडिशा में खरीफ सीजन की चावल की खरीद 31 मार्च को समाप्त हुई। यहां 3.95 मिलियन टन खरीद की गई, जो एक साल पहले 4.42 मिलियन टन से कम थी। आंध्र प्रदेश में 36 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है, वहां भी खरीद समाप्त हो गई है। यह एक साल पहले के 2.1 मिलियन टन के मुकाबले 1.34 मिलियन टन थी।

पिछले साल इतना खरीदा गया था

सरकार ने 2022-23 में सभी खरीफ, रबी और जायद सीजन से कुल 56.87 मिलियन टन चावल खरीदा था। कृषि मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि देश में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में चावल का उत्पादन 2022-23 में 125.52 मिलियन टन से 2023-24 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के दौरान 1 प्रतिशत कम होकर 123.82 मिलियन टन हो गया है। अनुमान में जायद की फसल को शामिल नहीं किया गया है, जो रबी की फसल के बाद बोई जाती है। वर्ष 2022-23 में, जायद सीजन से चावल का उत्पादन 10.24 मिलियन टन था। चावल की खरीद सरकारी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की कुंजी है क्योंकि इसने 2021-22 में कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम में गेहूं की जगह ले ली है।

खंडवा की सीड्स कंपनी ने बनाया-खरगोन के किसानों के नाम से बीज उत्पादन प्रोग्राम

कंपनी और बीज प्रमाणीकरण की मिली भगत से नकली सोयाबीन बीज बिकने को तैयार

खरगोन में अन्नदाता के साथ धोखाधड़ी नेता की कम्पनी बना रही नकली बीज

खरगोन। जागत गांव हमार

किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन इन्हीं के साथ अक्सर धोखाधड़ी की जाती है। हालांकि यह कई बार पढ़ने में आता है कि बीज निर्माण करने वाली कम्पनियों ने किसानों के साथ धोखा किया। किसानों को नकली खाद-बीज उपलब्ध कराया गया है। लेकिन सत्ता में बैठी भाजपा के नेता की ही बीज कंपनी ने जिले में किसानों के साथ धोखाधड़ी कर दी है। इसकी शिकायत किसानों ने लिखित रूप से कलेक्टर को की है। दरअसल, खंडवा के भाजपा नेता की बीज कंपनी ने पहले तो खरगोन के किसानों के खेत में सोयाबीन बीज उत्पादन का प्रोग्राम बनाया। इसके बाद न किसानों ने बीज खरीदा न उन्हें बीज प्रमाणीकरण की जानकारी मिली। ऐसे में शहर में सीड्स कंपनी और रसूखदारों की मिलीभगत का फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। मिटावल तहसील झिरन्या के कुछ किसानों ने सारस एग्रो इंडस्ट्रीज के खिलाफ गुमराह करने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि खंडवा के दोंदवाड़ा स्थित सारस एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा वर्ष 2023-24 के खरीफ सीजन में गांव के 100 से ज्यादा किसानों के नाम से फर्जी दस्तावेज लगा कर सोयाबीन बीज उत्पादन का कार्यक्रम दर्शा कर बड़े पैमाने पर नकली बीज को प्रमाणीकरण करवा कर बेचा जा रहा है। जबकि गांव के किसानों द्वारा न ही उक्त बीज कंपनी से खरीद कर बोवनी की गई थी न ही कोई उपज उक्त कंपनी को बेची गई है।

खंडवा में नकली बीज का कारोबार

खंडवा के साथ आस-पास के जिलों में दो सैकड़ा से अधिक बीज उत्पादन समितियां एवं कंपनियां कार्यरत हैं जिनमें से अधिकतर कंपनियां सोयाबीन बीज की सप्लाई स्थानीय मार्केट से ज्यादा महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में कर रही है। कुछ कंपनियां तो कर्नाटक सरकार को सरकारी बीज विक्रय केंद्रों और सहकारी समितियों में बिक्री के लिए भी सोयाबीन बीज सप्लाई कर रही हैं।

इन किसानों ने लगाई गुहार

खरगोन जिले और खंडवा जिले की सीमा से लगे क्षेत्र झिरन्या तहसील के मिटावल गांव के किसान गजेंद्र सिंह राजपूत, भूपेंद्र पटेल, राहुल राठौड़, सुनील पटेल, कड़वा सुपड़ु, बंदर छज्जू, संदीप कैलाश राठौर आदि ने खरगोन कलेक्टर एवं संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी खंडवा को शिकायत कर बता गया की खंडवा जिले की सीड्स कंपनी द्वारा उनके एवं उनके परिजनों के दस्तावेजों का बिना अनुमति उपयोग कर बीज उत्पादन प्रोग्राम बताया गया है, जिसके कारण उन्हें सोयाबीन फसल खराब होने के बावजूद कराए गए फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिल पाया है जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

होनी चाहिए सख्त कार्रवाई

किसानों का कहना है कि बीज प्रमाणीकरण संस्थान के बीज निरीक्षक भी कंपनियों के साथ मिलकर अन्नदाता के साथ धोखाधड़ी में सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि नियमानुसार बीज प्रमाणीकरण विभाग के निरीक्षक को कंपनी द्वारा पंजीयन किए गए बीज उत्पादक कृषकों के खेत में पहुंच कर फसल का निरीक्षण करना अनिवार्य होता है। बिना निरीक्षण रिपोर्ट के बीज उत्पादन होना ही पूरी तरह गलत है। ऐसे में बीज प्रमाणीकरण संस्थान के जिम्मेदार भी कंपनियों के साथ मिल कर अन्नदाता कृषकों को धोका दे रहे हैं। इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए।

राजनैतिक रसूख के चलते नहीं हो पाती कार्रवाई

किसानों ने जिस सारस एग्रो इंडस्ट्रीज के खिलाफ उनके नाम एवं दस्तावेजों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए है। वह कंपनी जिले के सत्ताधारी दल के कद्दावर नेता की बताई जा रही। जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जिले की एकमात्र अनारक्षित विधानसभा सीट से जमकर टिकट के लिए जोर आजमाइश की थी। वहीं टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय नामांकन भी किया था, परंतु बाद में संगठन के अपने निकटस्थ नेता के कहने पर अंतिम समय में पर्चा वापस ले लिया था। जहां उनकी कंपनी में बड़े पैमाने पर किसानों के फर्जी दस्तावेज लगा कर नकली बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं ही ऐसे में कहीं न कहीं रसूख और राजनीति के दम पर किसानों के साथ छल किया जा रहा है।

- खरगोन जिले के मिटावल और कुछ गांव के किसान सोयाबीन पंजीयन की शिकायत लेकर आए थे। मामले की जांच करवा रहे हैं। दोषियों पर छोड़ा नहीं जाएगा।

गोपाल सिंह नरगिस, प्रभारी संभाग, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी खंडवा

- जानकारी मिली है। किसानों के नाम से बीज उत्पादन प्रोग्राम दर्शाकर की गई अनियमितता की जा रही है। गंभीर मामला है। टीम गठित कर जांच करवाएंगे।

-मांगीलाल चौहान, उप संचालक कृषि विभाग, खरगोन

पांच ऐसी फसल जिनकी लागत कम और मुनाफा ज्यादा

गर्मी में सिंचाई की व्यवस्था कम नहीं रहने पर अधिक किसान खेती नहीं कर पाते

अप्रैल में फसल-सब्जी की खेती से किसानों की होगी बंपर कमाई

भोपाल। जागत गांव हमार

अप्रैल का महीना चल रहा है। देश में इस वक्त गर्मी की शुरुआत होती है। इस समय रबी फसलों की कटाई होती है और गरमा सब्जियों की खेती की जाती है, चूंकि यह मौसम गर्मी का होता है, तापमान अधिक रहता है इसलिए सब्जियों की या फसलों की अच्छे से देखभाल की जानी चाहिए। साथ ही इस मौसम में सब्जियों की खेती अधिक की जाती है क्योंकि इसकी मांग भी अधिक रहती है। गर्मी में सिंचाई की व्यवस्था कम नहीं रहने पर अधिक किसान खेती नहीं कर पाते हैं। इसलिए सब्जियों की खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस खबर में हम पांच ऐसी फसलों की खेती के बारे में बता रहे हैं, जिनकी खेती में लागत कम आती है और इससे किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मकई की मांग में काफी तेजी आई है इसलिए इसकी खेती काफी फायदेमंद मानी जाती है। पॉल्ट्री के साथ-साथ पशु चारे और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग में इसकी अच्छी खासी मांग है। गर्मियों में इसका उत्पादन अच्छा होता है साथ ही कम पानी में भी इसकी खेती हो जाती है। इसलिए किसान गर्मियों के लिए इसकी उपयुक्त किस्मों का चयन कर इसकी खेती कर सकते हैं। इनमें बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की किस्में भी शामिल हैं।

मूली की खेती- गर्मियों में लोग सलाद खाना काफी पसंद करते हैं और सलाद के तौर पर मूली की मांग खूब होती है। मूली की कुछ ऐसी भी किस्में आपको बाजार में मिल जाएंगी जो गर्मी के मौसम में अच्छा उत्पादन देती है। इनमें चेतकी मूली और बैशाखी मूली किस्में शामिल हैं जो गर्मी में भी अच्छी उपज देती है। मूली एक कम अवधि की खेती होती है। इसकी उन्नत किस्मों की बुवाई करने के बाद यह 30-40 दिनों में तैयार हो जाती है। गर्मियों में मूली की मांग अधिक रहती है कि इसलिए बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। इससे किसानों को अच्छी कमाई होती है।

चारे के लिए करें लोबिया की खेती-

गर्मियों में मौसम सूखा रहता है ऐसे में हरे चारे की कमी हो जाती है। लोबिया की खेती किसानों की इस समस्या को दूर कर सकती है। लोबिया की खेती दाने और चारे के लिए की जाती है। इसकी खेती में कम पानी की जरूरत होती है। बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती करने से किसानों को अच्छी उपज प्राप्त होती है। लोबिया की खेती करने के लिए खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए और जमीन को समतल बनाना चाहिए, क्योंकि जल भराव होने पर फसल के किए समस्या हो सकती है।

चौलाई की खेती

चौलाई की खेती किसान साल में दो बार कर सकते हैं। बरसात के मौसम और गर्मियों के मौसम में इसकी खेती की जाती है। इसके उन्नत किस्मों की बोवनी अप्रैल महीने के अलावा मार्च और फरवरी में भी कर सकते हैं। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खाने के लिए होता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इसके गुणों के कारण बाजार में इसकी मांग अच्छी रहती है और दाम भी अच्छे मिलते हैं।

खीरा की खेती

गर्मियों के मौसम में सबसे अधिक इसकी मांग होती है। बाजार में यह खूब बिकता है और लोग सलाद के तौर पर इसे खूब खाते हैं। इसलिए गर्मियों में इसकी मांग भी खूब होती है। अप्रैल महीने में किसान इसकी खेती करते हैं और अच्छी मात्रा में उपज भी प्राप्त होती है। अच्छी उपज पाने के लिए बलुई या दोमट मिट्टी में इसकी उन्नत किस्मों की खेती करनी चाहिए। खीरा के खेत में जमाव नहीं होता है। गर्मियों में मांग अधिक रहने के कारण इसकी कीमत भी अच्छी रहती है और किसानों को अच्छी कमाई मिलती है।

इंदौर के भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास

एनआरसी 197 किस्म का सोयाबीन अब मध्यप्रदेश में करेगा कुपोषण का खात्मा

भोपाल। जागत गांव हमार

बिना प्रोसेसिंग के सीधे खाए जा सकने वाले सोयाबीन की खेती अब उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी हो सकेगी। इंदौर के भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने लम्बे अनुसंधान के बाद ऐसे सोयाबीन की पहली किस्म विकसित करने में कामयाबी हासिल की है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों का कहना है कि प्रोटीन से भरपूर यह किस्म पहाड़ी क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। 'एनआरसी 197' नाम की इस किस्म को विकसित करने वाले दो सदस्यीय अनुसंधान दल में शामिल प्रधान वैज्ञानिक डॉ. विनीत कुमार ने बताया, सीधे खाए जा सकने वाले सोयाबीन की किस्में मध्य भारत और दक्षिण भारत के लिए पहले ही विकसित की जा चुकी हैं। यह पहली बार है, जब उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए इस तरह के सोयाबीन की किस्म विकसित की गई है। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु के मद्देनजर विकसित 'एनआरसी 197' नामक यह किस्म कुनिट्ज ट्रिप्सिन इनहिबिटर से मुक्त है।

फ्री सोयाबीन की ये किस्म

आईआईएसआर में सोयाबीन की इस किस्म के विकास से जुड़े अनुसंधान में प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अनीता रानी भी शामिल थीं। उन्होंने बताया कि आम किस्मों में पाए जाने वाले केटीआई के चलते सोयाबीन को सीधे नहीं खाया जा सकता।उसे खाने से पहले उबालने और ठंडा किए जाने की जरूरत होती है। अगर केटीआई-युक्त सोयाबीन को बिना इस प्रोसेसिंग से पहले सीधे खाया जाता है तो इसके पाचन में दिक्कत हो सकती है, पर 'एनआरसी 197' के साथ यह समस्या नहीं है क्योंकि यह केटीआई से मुक्त है।

112 दिनों में पककर तैयार हो जाती है फसल

सोयाबीन की एनआरसी 197 किस्म में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है. इसकी खेती को बढ़ावा देकर पहाड़ी इलाकों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है। अधिकारियों ने बताया कि 'एनआरसी 197' की एक खूबी यह भी है कि इसकी फसल पहाड़ी इलाकों में उगाई जाने वाली सोयाबीन की आम किस्मों के मुकाबले जल्दी पक जाती है। यह किस्म पहाड़ी इलाकों में बोवनी के बाद 112 दिनों में पककर तैयार हो जाती है।

जैव सुरक्षा प्रबंधन : जानवरों को रोगों से बचाने का उचित प्रबंधन

» डा. कविता रावत
» डॉ. अर्चना जैन
» डॉ. ज्योत्सना शक्करपुडे
» डॉ. रंजीत आइच
» डॉ. दीपिका डायना जे.ए.
» डॉ. मनोज कुमार अहिरवार
» डॉ. आम्रपाली भिमटे
» डॉ. श्वेता राजोरिया
» डॉ. नरेश कुरेचिया
» डॉ. जोयसी जोगी
» डॉ. मधु शिवहरे

पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू

जैव सुरक्षा प्रबंधन अभ्यास है जो संक्रामक रोगों को झुंड में या परिसर में ले जाने से रोकता है। जैव सुरक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यमों से जानवरों में रोग पैदा करने वाले एजेंटों के संचरण को रोकना है। जैव सुरक्षा प्रबंधन प्रथाओं को परिसर में और भीतर जीवों और उनके वैक्टरों की को कम करके बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जैवसुरक्षा कार्यक्रम अपनाने के अनेक लाभ हैं। एक प्रभावी कार्यक्रम खेत की लागत दक्षता में सुधार कर सकता है, उत्पादक की प्रतिष्ठा में सुधार कर सकता है और उत्पादक को झुंड की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाए रखने की अनुमति दे सकता है। जैव सुरक्षा कार्यक्रम उपलब्ध रोग नियंत्रण के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है, और कोई भी रोग निवारण कार्यक्रम इसके बिना काम नहीं करेगा।

रोग: इसके कारण और यह कैसे फैलता है: जैव सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले पहले कदमों में से एक यह सीखना है कि बीमारी का कारण क्या है ताकि बीमारी को रोका जा सके। रोग और खराब स्वास्थ्य बैक्टीरिया के कारण होते हैं जैसे कि केसियस लिम्फैडेनाइटिस का कारण बनते हैं। वायरस द्वारा, जैसा कि कैप्रिन आर्थराइटिस एन्सेफलाइटिस के मामले में होता है या कोक्सीडिया जैसे परजीवियों द्वारा। रोग का प्रसार बहुघटकीय है। यह मेजबान कारकों (स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा स्थिति, आदि), पर्यावरणीय कारकों, और रोग एजेंट पर निर्भर करता है। एक अच्छे जैव सुरक्षा कार्यक्रम की कुंजी बीमारी के संचरण को तोड़ना या उसके प्रभाव को कम करना है।

बकरी के झुंड में बीमारियों के प्रसार या संचरण में जिन मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए वे हैं। **1.** रोगग्रस्त बकरियों या रोग पैदा करने वाली स्वस्थ बकरियों का परिचय, जिन्हें वाहक पशु भी कहा जाता है। **2.** वाहनों, उपकरणों, कपड़ों और अन्य दूषित निर्जीव वस्तुओं से संक्रमण की संभावना। **3.** मृत पशुओं के शवों का उचित एवं समय पर निपटान। **4.** खाद्य पदार्थों और पानी का उचित प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे दूषित न हों। **5.** खाद का उचित रख-रखाव। **6.** गैर-पशुधन वाहक (पक्षी, कृंतक, कीड़े, बिल्लियाँ, आदि) का नियंत्रण।

एक प्रभावी जैवसुरक्षा कार्यक्रम के पहलू: रोग संचरण के सभी संभावित मार्गों के कारण एक प्रभावी जैव सुरक्षा कार्यक्रम को जिन मुद्दों का समाधान करना चाहिए वे जटिल हो सकते हैं। एक प्रभावी रोग नियंत्रण कार्यक्रम को निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए।

1. यातायात नियंत्रण, **2.** स्वच्छता, **3.** खाद्य सुरक्षा, **4.** व्यक्तिगत स्वच्छता, **5.** अच्छी प्रबंधन प्रथाएं (जीएमपी) और आम तौर पर स्वीकृत (जीए) स्वच्छता, **6.** गुणवत्ता आश्वासन/झुंड स्वास्थ्य, **7.** जैव आतंकवाद, **8.** अलगाव/संगरोध।

जैव सुरक्षा कार्यक्रम के पहले और सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक जिसे निर्माता की प्रबंधन योजना में शामिल किया जाना चाहिए, वह यह जानना है कि जीवित जानवरों और वध के समय दोनों में क्या सामान्य और क्या असामान्य है। नीचे दी गई तालिका में बकरियों में स्वास्थ्य और बीमारी के लक्षणों के उदाहरण शामिल हैं।

स्वास्थ्य अलर्ट: स्वस्थ बकरियाँ बीमारी के लक्षण, अच्छी भूख, ख़राब भूख, चमकदार कोट सुस्त कोट, बाल झड़ रहे हैं। मिलनसार अलगाव। चमकदार और साफ आंखें बहती आंखें। अच्छी तरह से वज़न घटाना। मजबूत टाँगें और पैर लंगड़ापन, जोड़ों में सूजन। गुलाबी मसूड़े एनीमिया। ठोस गोलीयुक्त मल दस्त। शरीर के किसी भी अंग में सूजन नहीं। जुगाली करना जुगाली करना सामान्य साँस लेना, कष्टदायक साँस लेना, खाँसी, तेजी से साँस लेना। बिना किसी कठिनाई के पेशाब करना।

जैव सुरक्षा उपाय: निम्नलिखित कुछ उपाय और प्रथाएं हैं जिन्हें उत्पादकों द्वारा सुरक्षा और झुंड स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाना चाहिए।

1. समस्याओं को ठीक करने के बजाय उन्हें रोकें। **2.** व्यक्तिगत और परिसर पशु पहचान कार्यक्रम लागू करें। **3.** अच्छे रिकॉर्ड रखें. रिकॉर्ड्स को खेत पर किए गए प्रबंधन प्रथाओं को ट्रैक और मान्य करना चाहिए।

अन्य जैव सुरक्षा उपाय जिन्हें एक प्रभावी कार्यक्रम में अपनाया जा सकता है। **1.** फ़ीड बंक में कभी भी कदम न रखकर खाद संदूषण को रोकने का प्रयास करें। **2.** जानवरों को दवा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, विशेष रूप से कई जानवरों पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित करें। **3.** बीमार पशुओं के संयम, उपचार और अलगाव के लिए स्वच्छ क्षेत्र प्रदान करें। **4.** बकरियों के बीमार होने या अप्रत्याशित रूप से मरने पर पशुचिकित्सक या पशु स्वास्थ्य कर्मी से परामर्श लें। **5.** आगंतुक यातायात की निगरानी और प्रबंधन करें। **6.** दूषित वाहनों और उपकरणों को साफ करें। **7.** उन झुंडों का स्वास्थ्य इतिहास जानें जहां नए जानवर खरीदे जाते हैं। **8.** झुंड में लाए गए जानवरों की स्वास्थ्य स्थिति जानें। **9.** पशुओं को साफ वाहनों में परिवहन करें। **10.** नए और बीमार जानवरों को संगरोधित और अलग करें। **11.** मृत स्टॉक का स्वच्छतापूर्वक निपटान करें। **12.** अन्य जानवरों के लिए एक नियंत्रण कार्यक्रम रखें जो बीमारी फैला सकते हैं (कृंतक, कीड़े, बाहरी परजीवी, आदि) **13.** खाद पर नियंत्रण रखें और उसका बार-बार निपटान करें। **14.** अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। **15.** चौकस रहें। **16.** पशुचिकित्सक के साथ ग्राहक-रोगी का अच्छा संबंध बनाए रखें।

उत्पादकों से लेकर उपभोक्ताओं तक, संपूर्ण कृषि उद्योग के लिए जैव सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जो उत्पादक अपने खेत में बीमारी के आगमन और प्रसार को सफलतापूर्वक नियंत्रित करते हैं, वे न केवल खुद को बल्कि पूरे उद्योग को भी लाभान्वित करते हैं। इस सफलता के लिए एक अच्छा जैव सुरक्षा कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। हालाँकि एक अच्छे जैव सुरक्षा कार्यक्रम को कई मुद्दों का समाधान करना होगा, यह एक ही समय में सरल और प्रभावी हो सकता है। बीमारी की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एक व्यक्तिगत और परिसर पहचान कार्यक्रम शामिल है। प्रबंधन प्रथाओं को ट्रैक और मान्य करना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, जानवरों के बीच क्रॉस-संदूषण को रोकना और नियमित मूल्यांकन शामिल करना चाहिए।

सेम-बेल वर्गीय सब्जी की आधुनिक खेती किसानों के लिए लाभदायी

» डा. लक्ष्मी प्रसाद भारद्वाज
» डॉ. शैलेश कुमार गुप्ता

अतिथि शिक्षक, सहायक प्राध्यापक, इं.गांकृ.वि.वि, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, कुनकुरी जशपुर (छत्तीसगढ़)

सेम बेल वर्गीय सब्जियों का एक प्रमुख फसल है। इसका वानस्पतिक नाम- डॉली कसलबलब किस्मटिपीकस तथा कुल-फेबेसी या लेग्यूमीनेसी है, यह लम्बे समय तक उपज देती रहती है एवं खाने के लिए के काफी महत्व है। सेम में बहुत से पोषक तत्व पाये जाते है जैसे थायमीन, विटामिन बी-6, नियासिन और पैंथोथेनिक एसिड जो हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। इसके अलावा सेम में कुछ ऐसे तत्व पाये जाते हैं, जो खून को साफ करने में सहायक होते हैं तथा त्वचा संबंधित रोग से बचाते हैं।

सेम की खेती छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में की जाती है। जिनमें से सरगुजा, कोरबा, जांजगीर, रायगढ एवं राजनांदगांव प्रमुख सेम उत्पादक जिला हैं।

जलवायु: सेम की अच्छी उपज के लिए ठण्डे जलवायु एवं लघु दिन कि आवश्यकता होती है तथा 20-25 डिग्री से.ग्रे. तापमान इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है।

भूमि: सेम की अच्छी उपज के लिए दोमट मृदा उत्तम मानी जाती है। मृदा का पी.एच. मान 5.3-6.0 तक उपयुक्त है।

खाद एवं उर्वरक: सेम फली वाली सब्जी होने के कारण इसे नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है तथा साधारणत: निम्न मात्रा में खाद एवं उर्वरक प्रयोग किया जाता है, जो निम्नानुसार है-

गोबर की खाद 20 टन/हे., नाइट्रोजन 20 कि.ग्रा./हे. फॉस्फोरस 40 कि.ग्रा./हे., पोटाश 40 कि.ग्रा./हे.

उन्नत किस्में: पुसा अर्ली प्रौलिफिक: इसमें फलियां गुच्छे में और अधिक मात्रा में लगती है यह अगेती किस्म है तथा हर मौसम में उगाया जा सकता है।

रजनी: इसकी फलियां हरी एवं गुच्छे में होती है प्रत्येक गुच्छे में 10-15 फलियां लगती है, प्रति हेक्टेयर औसत उपज 140-150 क्वि. तक मिल जाती है।

पुसा सेम 2: फलियां कोमल एवं रेशारहित होता है। यह 120 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है तथा औसत उपज लगभग 130-150 क्वि. तक मिल जाता है। फली छेदक कीट, चैंपा, जैसिड तथा विषाणु रोग के प्रति सहनशील होता है।

कल्याणपुर टाइप 1: यह स्वादिष्ट एवं शीघ्र पकने वाली किस्म है। इसकी औसत उपज प्रति हे. 130-150 क्वि. तक है।

खेत की तैयारी: खेत को मिट्टी पलट हल से 1 जुताई तथा 2-3 जुताई देशी हल से करके समतल कर लेना चाहिए एवं अन्तिम जुताई के पूर्व खेत में गोबर की खाद, फॉस्फोरस एवं पोटाश की पुरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को खेत में मिला देना चाहिए तथा शेष नाइट्रोजन की मात्रा को 25-30 दिन बाद दिया जाता हैं।

बोआई का समय: सेम की बीजों की बोआई फरवरी-मार्च तथा जून-जुलाई में की जाती है।

बीजदर: इसकी खेती के लिए 25-30 कि.ग्रा. बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है।

बोने की विधि: सेम की बोआई कतार में की जाती है, तथा कतार से कतार कि दूरी 1.5 मी. एव पौधे से पौधे की दूरी 60 से.मी. रखकर, मेढ़ो में 4-5 से.मी. की गहराइ में बीजों की बोआई कि जाती हैं।

सिंचाई एवं जल निकास: ठण्डी मौसम की फसल को 12-15 दिन की अन्तराल में तथा वर्षा कालीन फसल को आवश्यकतानुसार सिंचाई करते हैं एवं अत्यधिक वर्षा होने पर उचित जल निकास का प्रबंध किया जाता हैं।

निराई-गुड़ाई: बोआई की 20-25 दिन के अन्तराल में दो बार निराई-गुड़ाई कि आवश्यकता होती हैं।

पौधों को सहारा देना: जब सेम के पौधे बढ़ने लगे तब उसे सीधे कतार में बांस गाड़कर एवं रस्सी का जाल बनाकर या मंडप बनाकर सहारा देना चाहिए जिससे फलियां अधिक आती है और उपज अधिक मिलता है।

फसल सुरक्षा: कीट: फली छेदक: यह कीट कोमल फल्लीयों में छेदकर बीज एवं फलियों को खाता है, जिससे बीज एवं फलियां खाने योग्य नहीं रहता है। **नियंत्रण:** 0.2 प्रति. सेविन का प्रति ली. पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

एफिड: यह पौधे की उपरी कोमल भाग में चिपके रहते हैं तथा पौधे का रस चूसते हैं। जिससे पौधे कुरुप दिखाई देता है, लताओं में फूल एवं फलियां नहीं लगती।

नियंत्रण: एफिड की नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोरप्रिड 2.0मि.ली. प्रति लीटर पानी की घोल बनाकर छिड़काव करें।

रोग: चूर्णी फफूंदी: यह फफूंद पत्तीयों एवं फलीयों की उपरी सतह पर सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देते हैं तथा पत्तीयां पीली होकर सुख जाती है। **नियंत्रण:** इसकी नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्रा. प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए।

श्यामव्रण (एन्थ्रेकनोज): -यह फफूंद जनित रोग होता है इस रोग के लक्षण सर्व प्रथम तना, पत्तियों एवं फलियों पर लाल एवं भूरे धब्बे के रूप में दिखाई देता है। **नियंत्रण:** इसकी रोकथाम के लिए बाविस्टिन 0.1 प्रतिशत का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फलियों की तुड़ाई-सब्जी के रुप में खाने के लिए पूर्ण विकसित कोमल फलियों की तुड़ाई करना चाहिए। **उपज:** सेम की उपज फसल की देखरेख एवं भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। तथा इसकी औसत उपज 100-130 क्वि. प्रति हे. तक मिल जाता है।

पशुओं में रेबीज से बचाव के उपाय

» डा. मानसी शुक्ला
सहायक प्राध्यापक पशु शरीर संरचना विभाग, पशु महाविद्यालय, रीवा

रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, जिससे हमें अपने पशुओं को बचाना चाहिए। यह एक विषाणु जनित रोग है, जो पशुओं में एवं मनुष्यों में उनके केंद्रीय स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। यह विषाणु द्वारा होता है और स्तनधारी जीवों में पाया जाता है। यह बीमारी, ग्रसित पशु द्वारा काटे जाने से फैलती है। यह विषाणु, ग्रसित जीव के लार और मस्तिष्क में पाया जाता है। विषाणु घाव के मध्य से आंख, नाक एवं मुख के श्लेष्म झिल्ली में प्रवेश करके भी फैलता है। यह सामान्य त्वचा को पार नहीं कर सकता द्य यह विषाणु घाव के द्वारा शरीर में प्रवेश करने के बाद संभागीय स्नायु तंत्र से केंद्रीय स्नायु तंत्र तक पहुंचता है और इसका इनक्यूबेशन पीरियड औसतन 2 सप्ताह से 6 साल तक होता है। इसकी विकास अवधि विषाणु की मात्रा एवं मस्तिष्क से घाव की दूरी पर निर्भर करती है अर्थात, मस्तिष्क के जितना पास घाव होता है बीमारी के लक्षण उतनी जल्दी सामने आने लगते हैं।

बीमारी के लक्षणों में काफी अंतर पाया जाता है- जैसे लक्षण जीव के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में देखे जाते हैं। एक रूप है आक्रामक रूप और दूसरा है मूक रूप। आक्रामक रूप में पशु अत्यधिक आक्रामक और उत्तेजित हो जाता है और हवा में झपटना लगता है एवं चिडचिडा दिखने लगता है, जबकि मूक रूप, जिसे हम डंब फॉर्म बोलते हैं, उसमें रोगी चुपचाप एक कोने में शांति से पड़ा रहता है। उसको मति भ्रम का दोष हो जाता है। उसकी आवाज में परिवर्तन हो जाता है और मुंह से झाग निकलने लगता है। वह लडखडाने भी लगता है और आखिर में रोगी पक्षघात का शिकार हो जाता है और 7 दिनों के अंदर श्वसन तंत्र निष्काम होने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है।

हम अपने पशुओं को कुछ सावधानियां बरत कर इस भयानक बीमारी से बचा सकते हैं। बचाव के उपाय इस प्रकार हैं - कुत्तों में जन्म के तीन माह पश्चात तथा इसके बाद प्रत्येक वर्ष रेबीज निरोध टीक लगवाएं। संभावित पागल कुत्ते अथवा जानवर को बांधकर 14 दिनों तक उसके व्यवहार में परिवर्तन, पागलपन एवं मृत्यु हेतु निरीक्षण करें। पागल पशु या कुत्ते द्वारा काटे गए पशुओं में तुरंत बचाव हेतु, पागल कुत्ते या पशु द्वारा काटे गए भाग को फिनायल युक्त लाल साबुन, कास्टिक सोडा वाले साबुन के पानी से अच्छे से धोएं तथा ऐसे कई बार उस घाव को धोए। इस प्रकार हम अपने स्वस्थ पशुओं को इस भयानक बीमारी से बचा सकते हैं। याद रखें बचाव ही उपाय है।

जागत गांव हमार अपने इस अंक में किसानों को एक ऐसे अमरूद की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं जो जापानी प्रजाति का है। इसकी पैदावार रतलाम जिले में की जा रही है। यह अमरूद रेड डायमंड के नाम से अपनी पहचान बना रहा है। खाने में बहुत सॉफ्ट है। अंदर से तरबूज जैसा लाल। मीठे और खट्टा भी है, पर स्वाद लाजवाब है। बिना बीज का अमरूद है। इस अमरूद की खेती में लागत से 3 गुना मुनाफा है। इसकी खेती किसान डीपी धाकड़ कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में जापान के रेड डायमंड अमरूद की खेती

बिना बीज का तरबूज जैसा लाल, सीसीटीवी से निगरानी, लागत से तीन गुना मुनाफा

रतलाम के किसान ने 20 बीघा में अमरूद का बगीचा लगाया

रतलाम। जागत गांव हमार

डीपी धाकड़ ने बताया कि यूट्यूब के जरिए जापान के रेड डायमंड अमरूद की जानकारी मिली थी। इसके बाद इंटरनेट के माध्यम से ही गुजरात में इस अमरूद के पौधे मिलने की जानकारी भी प्राप्त हुई। फिर वहां जाकर पौधे और पैदावार के बारे में समझा। जून 2022 में अपने 20 बीघा खेत में करीब 4 हजार पौधे लाकर लगाए। एक पौधा की कीमत 250 रुपए थी। किसान धाकड़ के अनुसार पौधों को लगाने के बाद साल भर में फल आना शुरू होते हैं, लेकिन पूरी तरह से पौधे लगने के 3 साल बाद ही आपकी मेहनत बड़े फल के रूप में नजर आएगी। अभी शुरुआत में करीब 20 से 25 पौधे से फल लेकर बेच चुके हैं।

एक पौधे पर 2 हजार का खर्च

जापानी रेड डायमंड अमरूद के पौधे की देखरेख से लेकर बड़ा करने में एक पौधे पर लगभग 2 हजार रुपए तक का खर्च आ जाता है, जिसमें दवाई, कीटनाशक, बीज के अलावा फल को स्क्रेच ना आए, इसलिए आसपास की पत्तियां भी समय-समय पर हटाना पड़ती है। पौधों की ग्रोथ सही हो, इसके लिए साल में 2 बार इसकी छंटाई भी करनी पड़ती है। फल चीकू के साइज का हो जाए तो इसे फोम बैग के साथ पेपर से कवर (ढकना) करना पड़ता है। इससे अमरूद में पकाव अच्छा आता है। दाग, धब्बे भी नहीं लगते। फल का धूप, कीट व पक्षियों के डंक से भी बचाव हो जाता है।

पौधों की आपस में दूरी 7 फीट

पौधे आपस में टकराए नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 7 फीट रखी जाती है। बीच की रो (कतार) की दूरी 13 फीट रखनी पड़ती है। 13 फीट रखने का भी कारण है। किसान धाकड़ बताते हैं कि वर्तमान समय में हम जब खेती करते हैं तो हकाई, जुताई, स्प्रे सारे आधुनिक टेक्निक वाले पंप है। जो ट्रैक्टर से ऑटोमैटिक दवाइयों का स्प्रे किया जाता है, इसलिए पौधों की रो की दूरी रखना आवश्यक है, ताकि ट्रैक्टर आसानी से पौधों के बीच में चलाया जा सके।

जानिए देसी अमरूद-रेड डायमंड में अंतर

देसी अमरूद- आम अमरूद जिसे इलाहाबादी सफेदा कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में देसी जामफल कहा जाता है। देसी अमरूद में बीज होते हैं। दांत में समस्या होने वाले इस अमरूद को खाने से परहेज करते हैं। देसी अमरूद मौसम के अनुकूल ही होते हैं। देसी जामफल एक्सपोर्ट फल की गिनती में नहीं आता। इसका कारण यह है कि यह अमरूद दो से तीन दिन में खराब हो जाता है।

रेड डायमंड अमरूद- जापानी रेड डायमंड अमरूद में बीज नहीं होते हैं। इस वैरायटी के अमरूद की डिमांड ज्यादा है। इसे बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। जापान का रेड डायमंड अमरूद की सेलिब्रिटी में अच्छी खासी डिमांड होने से इसको सहेजकर डिलीवरी की जाती है। इसी कारण इसका रेट (मूल्य) भी अच्छे मिलते हैं।

दिल्ली में रेड डायमंड की ज्यादा डिमांड

जापानी रेड डायमंड अमरूद की सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली में है। सेलिब्रिटी इसे ज्यादा पसंद करते हैं। रतलाम के किसान से दिल्ली के व्यापारी सीधे कनेक्ट रहते हैं। पूरी तरह से फल आने पर किसान व्यापारी से डिमांड लेकर शाम 5 बजे दिल्ली के लिए कार्टून (खोखे) में प्लास्टिक की पैकिंग के साथ अमरूद को पैक करते हैं। अगले दिन दिल्ली में डिलीवरी हो जाती है। कई व्यापारी तो किसान को सीधे वीडियो कॉल कर फल की साइज देख ऑर्डर दे देते हैं।

एक पौधे में 70 से 80 फल

सबसे पहले 2 बाय 2 का गड्?ढा खोदा जाता है। उसमें पौधा रोपा जाता है। समय-समय पर आवश्यक कीटनाशक दवाई, स्प्रे, देखरेख की जाना आवश्यक है। जब पौधा 3 साल का होगा तो इसमें 70 से 80 फल आएंगे। 4 से 5 साल का पौधा होने पर 100 से 125 तक फल आएंगे। पौधों की देखरेख के लिए ड्रिप सिंचाई, पानी, मजदूरी, लोहा तार सभी को मिलाकर 8 से 10 लाख रुपए बीघा का खर्चा होता है। किसान धाकड़ के अनुसार पौधों की लागत के साथ ही देखरेख की मेहनत भी ज्यादा है।

जितना स्वादिष्ट, उतना अच्छा दिखना भी जरूरी

किसान धाकड़ के अनुसार फल जितना स्वादिष्ट होता, उतना ही अच्छा दिखना भी चाहिए ताकि उसका रेट मिल सके। कई व्यापारी तो सीधे खेत से ही ऑर्डर बुक करा देते हैं। धाकड़ बताते हैं कि कई व्यापारियों को वीडियो कॉल से फल के बारे में बताया जाता है। व्यापारी फल की साइज व क्वालिटी देखता है। फिर खरीदने को तैयार हो जाता है। कई बार हम सीधे ट्रक लोड कर व्यापारी के पास भेज देते हैं। अब परंपरागत खेती में मुनाफा नहीं के बराबर रह गया है। हमारा रतलाम खेती में बहुत आगे है। उसी को लेकर नई-नई खेती करते रहते हैं।

मार्च से जून के बीच लगाया जाता है पौधा

जापानी रेड डायमंड अमरूद का पौधा मार्च से लेकर जून माह के बीच लगाया जाता है। खासकर गर्मी के मौसम में यह पौधा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को देख लगाया जाता है। ठंड और बारिश में यह पौधा इसलिए मालवा की काली मिट्टी में नहीं लगाया जाता, क्योंकि यह समय इसे बोने के लिए अनुकूल नहीं रहता और पौधे की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है।

भूसा और ग्रीन खाद बनाकर किसान हो रहे मालामाल

छिंदवाड़ा के मोहन ने पराली को ही बना दिया लाभ का धंधा

दयानंद चौरसिया। छिंदवाड़ा

पराली जलाने के मामले में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर मध्यप्रदेश है। पराली से एक नहीं, कई समस्याएं पैदा होती हैं। पर्यावरण तो खराब होता ही है, खेत की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। लेकिन अब मध्यप्रदेश के महाकोशल क्षेत्र में किसानों ने पराली को लाभ का सौदा बना लिया है। किसानों ने पराली से मालामाल होने का रास्ता खोज लिया है। किसान अब पराली को जलाने के वजाय उसे भूसे के रूप में व्यापारिक उपयोग करने लगे हैं। इसके अलावा पराली से ग्रीन खाद बनाने के साथ ही कई किसान मालामाल हुए हैं।

प्रयोग से हो रहा दोगुना फायदा

मध्य प्रदेश में मक्के की फसल काफी उगाई जाने लगी है। छिंदवाड़ा जिले के कुंडाली कला गांव के किसान मोहन रघुवंशी ने पराली जलाने की जगह उसका ऐसा प्रयोग किया कि अब उसे दोगुना फायदा हो रहा है। दरअसल, मक्के की फसल के बाद किसान ने बीच में सेम की फसल लगा दी। सेम की फसल को खड़ा रखने के लिए स्टैंड रॉड की जरूरत पड़ती है, ताकि जमीन पर उसकी बेल ना चल सके। किसानों ने उनकी जगह पर मक्के के पौधों का उपयोग किया है। मोहन रघुवंशी ने सेम की बेल को मकई के पौधों के ऊपर चढ़ा दिया ताकि बेलों को दूसरे सहारे की जरूरत ना पड़े। इसकी वजह से किसान के स्टैंड रॉड का खर्च बचा और बाद में इस पर ही प्लाऊ चलाकर ग्रीन खाद भी बना लिया।

पराली का भूसा बनाकर अन्य राज्यों में कर रहे आपूर्ति

आमतौर पर फसल काटने के बाद खेतों में पराली जलाने के लिए आग लगा दी जाती है। जिसकी वजह से खेतों में लाभ पहुंचाने वाले कीट और सूक्ष्म तत्व भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पराली से मुनाफा भी कमाया जा सकता है। बामनवाड़ा के किसान गोवर्धन चंद्रवंशी ने पराली से भूसा बनाकर व्यापार शुरू किया है। उन्होंने बताया कि पहले वे पराली जला दिया करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने पराली से भूसा बनाना शुरू किया। अब भूसा छिंदवाड़ा जिले के अलावा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में सप्लाई करते हैं, जिससे उन्हें लाखों रुपए का मुनाफा हो रहा है।

खेतों में बनाई जा रही पराली से ग्रीन खाद

छिंदवाड़ा उद्यानिकी कॉलेज के डीन डॉ. विजय पराड़कर ने बताया कि पराली से अपने खेतों में ही ग्रीन खाद बनाई जा सकती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होगी। इसके लिए बाजार में मिलने वाला डी कंपोजर का एक डिब्बा काफी होता है, जिसे 120 लीटर पानी में मिलाना होता है। इसके साथ में 1 किलो बेसन और 1 से 2 किलो गुड़ डालना है। जिसे घड़ी की दिशा में लकड़ी के माध्यम से चलाना होता है। ऐसे ही लकड़ी के माध्यम से 4 से 5 दिन तक दिन में तीन बार चलाएं। जब 5 से 6 दिन में इस घोल में कीटाणु दिखें और बदबू आने लगे तो इसका खेतों में छिड़काव कर देना चाहिए। 8 से 10 दिन में पराली गलकर ग्रीन खाद में तब्दील हो जाती है।

पराली से बना रहे ईंट

कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग ब्रिक्स का होता है। आमतौर पर ब्रिक्स मिट्टी के बनाए जाते हैं। लेकिन अब इनमें पराली का उपयोग किया जाने लगा है। जिस कारण किसान ब्रिक्स का काम भी शुरू कर रहे हैं। पराली को खेतों से काटने के बाद मशीन में उसे बारीक किया जाता है, जिसके बाद ब्रिक्स बनाने के काम में आने वाली मिट्टी में इसे मिलाकर आसानी से ब्रिक्स बनाई जाती है। जिससे किसानों को मिट्टी का आधा खर्च बच जाता है और ब्रिक्स मजबूत भी बनते हैं।

2026 की पहली तिमाही में चालू होने की उम्मीद

उज्जैन में 12 सौ करोड़ का निवेश करेगी पेप्सिको

भोपाल। जागत गांव हमार

पेप्सिको इंडिया देश में अपनी विस्तार योजना के तहत मध्य प्रदेश के उज्जैन में फ्लेवर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 1,266 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी बयान के अनुसार, 22 एकड़ में फैला यह संयंत्र भारत में पेप्सिको के पेय उत्पादन को बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निर्माण 2024 में शुरू होने वाला है। 2026 की पहली तिमाही में इसके चालू होने की उम्मीद है। पेप्सिको के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (भारत व दक्षिण एशिया) जागृत कोटेचा ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार के समर्थन से हमारा लक्ष्य क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बढ़ाने में प्रभावशाली प्रगति करते हुए अपनी पहुंच का विस्तार करना है। पेप्सिको इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेवरेजेज जॉर्ज कोवूर ने कहा कि नई इकाई भारत में कंपनी की दूसरी (फ्लेवर) विनिर्माण सुविधा होगी।कपंनी की वर्तमान में पंजाब के चन्नो में एक (फ्लेवर) विनिर्माण सुविधा है।

वियतनाम ने भी निवेश का प्लान

सनटोरी पेप्सिको वियतनाम बेवरेज सहित 60 से अधिक अमेरिकी उद्यमों की यात्रा के दौरान, पेप्सिको ने वियतनाम में दो नवीकरणीय ऊर्जा-संचालित संयंत्र बनाने के लिए 400 मिलियन का वादा किया। अमेरिकी खाद्य और पेय पदार्थ कंपनी पेप्सिको ने वियतनाम में अतिरिक्त 400 मिलियन का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निर्णय पिछले सप्ताह सनटोरी पेप्सिको वियतनाम बेवरेज सहित 60 से अधिक अमेरिकी उद्यमों के प्रतिनिधिमंडलों की वियतनाम यात्रा के दौरान सार्वजनिक किया गया था।

ये भी है प्लान

पेय और खाद्य निर्माण की लीडिंग कंपनी पेप्सिको ने कहा कि वह असम के नलबाड़ी में अपना पहला खाद्य विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पेप्सिको के एक बयान में कहा गया है कि 44.2 एकड़ में फैले इस प्लांट को 2025 में चालू करने का प्रस्ताव है और इसका लक्ष्य असम के 500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

पेप्सिको के प्लांट में 75 फीसदी रहेंगी महिलाएं

पेप्सिको इंडिया ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और क्षेत्र में महिलाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित और सहायक कार्य वातावरण बनाने के लिए असम कौशल विकास मिशन और रोजगार और शिल्पकार प्रशिक्षण निदेशालय के साथ एक त्रिपक्षीय रूप साइन किया है। कंपनी का लक्ष्य कम से कम 75 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व का है।

रतलाम में जैविक खेती से कम लागत में ले रहे ज्यादा फायदा

1500 से अब 2600 से अधिक खेती को प्राथमिकता के साथ कर रहे

अमित निगम। रतलाम

जैविक खेती की प्रति जिले के किसानों का रुझान बढ़ रहा है, ऐसा इसलिए की पिछले पांच सालों की बात करें तो 1500 से अब 2600 से अधिक इस खेती को प्राथमिकता के साथ कर रहे हैं। जो गेहूं, चना, दाल, फल-फ्रूड के अलावा सब्जियों का उत्पादन कर स्वयं के स्वास्थ्य के साथ ही जैविक विधि से खेती कर लागत कम आय अधिक प्राप्त कर रहे है। अब जिले के कई किसान जैविक उत्पाद शहर के अलावा अन्य जिलों से राज्य में मांग के अनुसार पहुंचा रहे है।

कृषि विभाग के आत्मा परियोजना अन्तर्गत जिले में 2600 किसान 1600 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें गेहूं, चना, सूरजमुखी के अलावा 18 प्रकार की सब्जियां और फल-फ्रूड का भी उत्पादन ले रहे हैं। जैविक उत्पादन की मांग अधिक उत्पादन कम है, फिर भी मांग के अनुसार स्थानीय बाजार के अलावा मध्यप्रदेश के इंदौर, उज्जैन और गुजरात, राजस्थान के अलावा पंजाब और दिल्ली तक भी जैविक उत्पाद रतलाम से पहुंचाया जा रहा है। आत्मा बीटीएम रतलाम विकासखंड के बीरपाल किरार सहित 2600 किसान से अधिक जैविक खेती कर रहे है। शहर के मध्य सप्ताह में एक दिन जैविक खेती से उत्पादित वस्तुओं का बाजार हर रविवार लगता है। मांग के अनुसार सब्जियां, सौफ, अजवाइन, दाल, गेहूं, गुड़ आदि सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं।

पेटेंट के लिए दिया आवेदन, बिल्डिंग निर्माण में हो सकेगा इस्तेमाल

मकान बनाने में कम होगी लागत, गर्मी में ठंड और ठंड में रहेगी गर्म

आईआईटी इंदौर ने गाय के गोबर से बनाया कांक्रीट जैसा मैटेरियल

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), इंदौर ने गाय के गोबर से तैयार प्राकृतिक फोमिंग एजेंट गोब-एयर तैयार किया है जो कंक्रीट जैसी आधुनिक निर्माण सामग्री में मिलने पर थर्मल इन्सुलेशन के रूप में कार्य करेगा। अधिकारियों के मुताबिक गाय के गोबर से बना प्राकृतिक फोमिंग एजेंट देश में अपनी तरह का पहला उत्पाद है। उन्होंने कहा कि इस पर्यावरण हितैषी उत्पाद को निर्माण सामग्री में मिलाए जाने से न केवल मकान बनाने की लागत घटेगी, बल्कि इमारतें गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहेंगी। यह अनूठा उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक है और बाजार में उपलब्ध रासायनिक-आधारित फोमिंग एजेंटों की तुलना में कहीं अधिक पर्यावरण और लागत-अनुकूल है। गोब-एयर को प्रोफेसर संदीप चौधरी और उनके पीएचडी छात्र संचित गुप्ता द्वारा विकसित किया गया है। प्रोफेसर चौधरी ने एक चर्चा में बताया, हम सोच रहे थे कि गाय के गोबर से आय बढ़ाकर गौशालाओं की किस तरह मदद की जा सकती है। इस दौरान हमें गाय के गोबर से प्राकृतिक फोमिंग एजेंट बनाने का विचार आया और हमने इसे अमलीजामा पहनाया।

बिल्डिंग निर्माण में मिलेगा फायदा

उन्होंने दावा किया कि गॉबएयर की मदद से कम वजन वाला कांक्रीट तैयार किया जा सकता है और इसमें बाजार में मौजूद भवन निर्माण सामग्री के मुकाबले 24 प्रतिशत कम लागत आती है। चौधरी ने बताया कि गोब-एयर मिलाकर तैयार भवन निर्माण सामग्री लाल मिट्टी से बनने वाली ईंटों और फ्लाई ऐश (कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से निकलने वाली राख) की ईंटों के मुकाबले खासी किफायती साबित होती है। यदि मुनाफे की गणना रुपयों में की जाए, तो गाय के गीले गोबर से होने वाली मौजूदा आय 1 रुपए प्रतिकिलो से बढ़कर 4 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक हो सकती है।

पेटेंट के लिए अर्जी दायर

टिकाऊ निर्माण सामग्री के रूप में गोब-एयर को कांक्रीट, ईंटों, टाइलों और ब्लॉकों में जोड़ा जा सकता है। गोब-एयर का उपयोग करके निर्माण अधिक पर्यावरण के अनुकूल होगा और ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग में अधिक अंक प्राप्त करने में सहायक होगा। आईआईटी की टीम वर्तमान में एक विनिर्देश तालिका विकसित करने पर काम कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि गोब-एयर की नवाचारी तकनीक के पेटेंट के लिए पहले ही अर्जी दायर की जा चुकी है।

माइक्रोग्रीन्स या छोटे पौधों की यह खेती स्वास्थ्य के अलावा आर्थिक रूप से भी लाभकारी

माइक्रोग्रीन्स की खेती फायदे का सौदा, सब्जियों की तुलना में 40 गुना अधिक देते हैं पोषक तत्व

हृदय रोग, मधुमेह के जोखिमों में कमी लाने में मददगार

भोपाल।

माइक्रोग्रीन्स अंकुरित सब्जियों के छोटे, युवा रूप हैं। ये अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये स्प्राउट के परिष्कृत रूप हैं। शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने वाले एंटीऑक्सीडेंट से यह भरपूर होते हैं। इसे हृदय रोग, मधुमेह के जोखिमों में कमी लाने में मददगार माना जाता है।

क्या आपने माइक्रोग्रीन्स के बारे में सुना है। दरअसल, माइक्रोग्रीन्स की खेती, एक आर्थिक तौर पर लाभकारी कृषि व्यवसाय है। इसमें छोटे-छोटे ग्रीन फोलिक या गेहूं जैसे पौधों को उगाने की प्रक्रिया होती है। इसके कई फायदे हो सकते हैं। दूसरी ओर इसे सुपरफूड भी कहते हैं। यह मानव शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पौधे विटामिन, खनिज, और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। इनमें अन्य सब्जियों की तुलना में 40 गुना अधिक पोषण तत्व होते हैं। विटामिन ए, सी, ई, के, बी6, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम के समृद्ध स्रोत के तौर पर इसे जाना जाता है। शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने वाले एंटीऑक्सीडेंट से यह भरपूर होते हैं। इसे हृदय रोग, मधुमेह के जोखिमों में कमी लाने में मददगार माना जाता है। दृष्टि में सुधार और रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को करें मजबूत करते हैं और त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। माइक्रोग्रीन्स को माइक्रोवेज भी कहा जाता है। ये अंकुरित सब्जियों के छोटे, युवा रूप हैं। ये अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये स्प्राउट के परिष्कृत रूप हैं।

क्या है माइक्रोग्रीन्स

माइक्रोग्रीन्स, सब्जियों और जड़ी-बूटियों के अंकुर से उत्पन्न होने वाली पहली टूलीफ्स हैं, जो लगभग 2 से 3 इंच लंबी होती हैं। । इनकी कटाई तब की जाती है, जब ये कुछ हफ्ते के हो जाते हैं और इनमें टूलीफ का पहला सेट विकसित हो जाता है। माइक्रोग्रीन्स, स्प्राउट्स की तुलना में बढ़ने में थोड़ा अधिक समय लेते हैं। शलजम, मूली, ब्रोकली, फूलगोभी, गाजर, चार्ड, लैट्यूस, पालक, अमरंथ, पत्तागोभी, चुकंदर, अजमोद और तुलसी सहित पौधों की कई किस्में हैं। इन्हें माइक्रोग्रीन के रूप में आसानी से उगाया जा सकता है।

माइक्रोग्रीन्स लोकप्रिय हो रहा

वैश्विक स्तर पर बढ़ते रोगों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए आजकल लोगों ने अपनी जीवनशैली के साथ खान-पान में भी बदलाव किए हैं। इसी के साथ माइक्रोग्रीन्स शब्द ने विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। लोग अब स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के तरीके अपना रहे हैं। नई तकनीकों का उपयोग करके पोषक फसलों और खाद्यान्न का उत्पादन किसानों द्वारा बहुत तेजी से किया जा रहा है। पौष्टिक फसलों की बात करें तो हरी सब्जियों का नाम सबसे पहले आता है। हरी सब्जियों में माइक्रोग्रीन्स के विभिन्न प्रकार घरों के किचन का हिस्सा तेजी से बनते जा रहे हैं। माइक्रोग्रीन्स या छोटे पौधों की यह खेती स्वास्थ्य के अलावा आर्थिक रूप से भी लाभकारी है।

खरबूज की खेती ने बदल दी किसान की किस्मत

70 दिनों की खेती! एक एकड़ में फसल से किसान ने लगभग डेढ़ लाख रुपए कमाए

प्रवीन नामदेव। जबलपुर

खेती के बारे में कहा जाता है कि ये किस्मत से होती है। कई बार किसान मौसम की मार से परेशान होते हैं, लेकिन कई बार लखपति भी बन जाते हैं। सिवनी के एक रहने वाले एक किसान ने थोक में आधे से भी कम कीमत में अपनी फसल बेची इसके बाद भी उसने लाखों रुपए कमा लिए। मात्र 70 दिनों की खेती में इस किसान ने एक एकड़ की फसल से लगभग डेढ़ लाख कमाए।

11वीं पास किसान आकाश साहू- सिवनी के आकाश साहू ने महज 11वीं क्लास तक ही पढ़ें हैं। पास ही के एक गांव में रहते हैं और खेती किसानी करते हैं। आकाश की उम्र अभी मात्र 28 साल है और वह लगभग 50 एकड़ के कृषि फार्म को संभालते हैं। इसमें वह कम समय में पैदा होने वाली फसलें खासतौर पर सब्जियों की खेती करते हैं। पहले आलू से लाखों रुपये कमाए अब खरबूजा ने उन्हें मालामाल किया तो कुछ दिनों बाद टमाटर की खेती से उन्हें मोटा फायदा होगा।

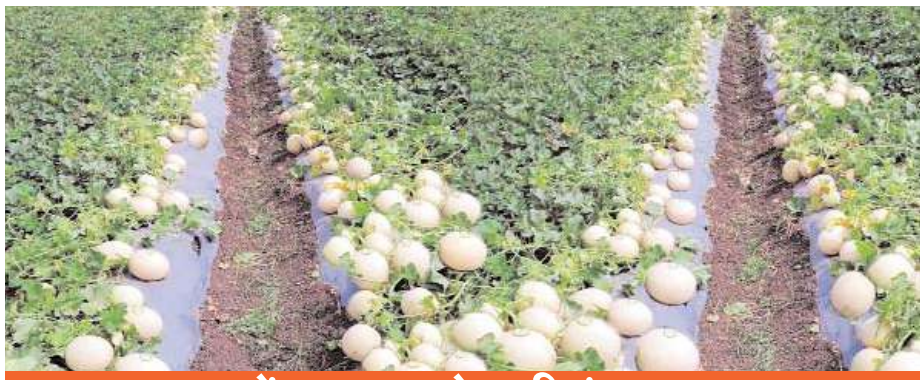

एक एकड़ में लगभग 70 से 80 क्विंटल तक उत्पादन

आकाश खरबूज की फसल लेकर सिवनी से जबलपुर की कृषि उपज मंडी में बेचने पहुंचे। आकाश साहू के लगभग 20 क्विंटल तरबूज 15 से 20 प्रति किलो के दाम में बिके हैं। हालांकि बाजार में यही तरबूज 40 से 50 किलो बिक रहा है। इसके बाद भी आकाश का कहना है कि इतने दामों में भी उन्हें पर्याप्त मुनाफा हो गया। आकाश ने बताया कि खरबूज की फसल मात्र 70 दिनों में तैयार हो जाती है, इसकी रोपाई जनवरी के महीने में की जाती है और अप्रैल के पहले सप्ताह में यह बाजार में आना शुरू हो जाती है। सामान्य फसल एक एकड़ में लगभग 70 से 80 क्विंटल तक उत्पादन देती है और मात्र 70 दिनों में एक एकड़ खेती से एक से डेढ़ लाख रुपए तक की फसल निकल आती है।

लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया

आकाश का कहना है कि खरबूज खत्म हो जाने के बाद वह टमाटर की खेती शुरू करेंगे। जिसका उत्पादन दो माह बाद आना शुरू होगा और पूरी बरसात टमाटर उन्हें उत्पादन देगा। आकाश साहू का कहना है कि वह और उनके जैसे ही दूसरे युवा एक साथ मिलाकर लगभग 50 एकड़ की खेती कर रहे हैं और इस खेती में उन्हें लाखों रुपए का मुनाफा होता है। वे आधुनिक खेती कर रहे हैं इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपनी खेती को उन्नत रखने के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है और वह पूरे 50 एकड़ में ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से पानी की सिंचाई करते हैं।

आलू की कांट्रैक्ट फार्मिंग

आकाश साहू ने बताया कि खरबूजे के पहले उन्होंने अपने खेत में आलू की कांट्रैक्ट फार्मिंग की थी। इसके लिए पेप्सी को नाम की एक कंपनी ने उनके साथ करार किया था। जिसमें आलू का बीज और दवाएं कंपनी ने ही मुहैया करवाई थी और जो भी उत्पादन निकला था उसे 15 रुपया प्रति किलो के भाव पर खरीद लिया था। इस साल उनके खेत में प्रति एकड़ 130 क्विंटल आलू निकला था।

50 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार

आकाश ने मात्र 11वीं तक पढ़ाई की है, यदि इस पढ़ाई के आधार पर भी नौकरी खोजने जाते तो उन्हें किसी ऑफिस में बेहद छोटी नौकरी मिलती लेकिन उन्होंने अत्याधुनिक तरीके से सब्जी की खेती शुरू करके न केवल खुद के लिए रोजगार बनाया है, बल्कि अभी 50 से ज्यादा दूसरे मजदूरों को भी नौकरी दे रहे हैं।

प्रदेश में जायद फसलों की बोवनी 2.52 लाख हे. पार

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में इस वर्ष 13 लाख 33 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जायद फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध 28 मार्च तक 2.52 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोवनी हो गई है। इसमें मुख्य रूप से मूंग, मूंगफली, मक्का, उड़द एवं धान फसल जायद में ली जाती है। सबसे प्रमुख एवं किसानों को मुनाफा देने वाली फसल मूंग है जिसे जायद में सबसे अधिक क्षेत्र में प्रदेश के किसान अपनाने लगे हैं। चालू जायद वर्ष 2024 में लगभग 11 लाख 58 हजार हेक्टेयर में मूंग लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 1.88 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मूंग की बोवनी हो गई है। वहीं गत वर्ष अब तक 1.79 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मूंग फसल ली गई थी। समर्थन मूल्य में बेहतर कीमत मिलने के कारण गत वर्ष किसानों को लाभ हुआ, इसे देखते हुए लक्ष्य में इस वर्ष 1 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की गई है तथा किसान मूंग लगाने के प्रति उत्साहित भी हैं। कृषि विभाग के मुताबिक देश एवं प्रदेश में सबसे अधिक मूंग फसल लेने वाला नर्मदापुरम जिला है। इस वर्ष यहां लगभग 2.95 लाख हेक्टेयर में मूंग लेने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे नम्बर पर रायसेन जिला है। यहां 1.65 लाख हेक्टेयर में मूंग ली जाएगी। तीसरे नम्बर पर हरदा जिला है यहां 1.45 लाख हेक्टेयर में मूंग ली जाएगी। इसी प्रकार नरसिंहपुर जिले में 1.40 लाख हेक्टेयर में मूंग लगाने का लक्ष्य है। सीहोर में 90 हजार, जबलपुर में 75 हजार, देवास में 44 हजार, गुना में 30 हजार, सागर में 25 हजार और कटनी में भी 25 हजार हे. में मूंग लेने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर राज्य में 11 लाख 58 हजार हेक्टेयर मूंग लक्ष्य के विरुद्ध 1 लाख 88 हजार हेक्टेयर में मूंग की बोवनी की गई है, जबकि गत वर्ष एक लाख 79 हजार 696 हेक्टेयर में बोवनी हुई थी।

60 दिन की मूंग किसानों के लिए काफी लाभदायक

कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में जायद की अन्य फसलों की बोवनी के तहत अब तक मूंगफली 5255 हेक्टेयर में, मक्का 9474 हेक्टेयर, उड़द 12539 हेक्टेयर एवं ग्रीष्मकालीन धान 37195 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है। 60 दिन की मूंग फसल किसानों के लिए काफी लाभदायक है।

मप्र में जायद की बोवनी मार्च 2024 (हेक्टे. में)

फसल	लक्ष्य	बोवनी
मूंग	1158758	188076
उड़द	87816	12539
धान	48565	37195
मक्का	21511	9474
मूंगफली	16824	5255

केंद्रीय बीज समिति ने सरसों की चार नई किस्मों को मंजूरी दी

केंद्रीय बीज समिति ने सरसों की चार नई किस्मों को दी मंजूरी

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय बीज समिति ने हाल ही में चार नई भारतीय सरसों किस्मों की अधिसूचना की घोषणा की है। इन किस्मों को खेती के लिए मंजूरी दे दी गई है और ये देश में सरसों क्षेत्र की वृद्धि और उत्पादकता में योगदान देने के लिए तैयार है।

1. **बीपीएम 11 (भरतपुर सरसों 11) (डीआरएमआर 2018-19):** रेपसीड-सरसों अनुसंधान निदेशालय (डीआरएमआर) द्वारा विकसित, भरतपुर सरसों 11 विशिष्ट कृषि-जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए उपयुक्त है। इस किस्म से किसानों को बेहतर पैदावार और प्रचलित बीमारियों और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की उम्मीद है।
2. **पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 35 (पीडीजेड 14):** प्रतिष्ठित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) द्वारा विकसित, पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 35 असाधारण विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जो इसे किसानों के लिए उपलब्ध सरसों की किस्मों के साथ एक मूल्यवान अतिरिक्त किस्म बनाता है। उच्च उत्पादकता क्षमता व अनुकूलन शीलता के साथ, पीडीजेड 14 से सरसों की खेती के परिदृश्य में अहम योगदान देने की उम्मीद है।
3. **पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 36 (पीडीजेड 15):** भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की एक और रचना, पूसा डबल जीरो मस्टर्ड 36 के सरसों क्षेत्र में गेम-चेंजर होने की उम्मीद है। इस किस्म में चाहे गए गुण हैं, जिनमें उच्च तेल सामग्री और जैविक और अजैविक तनावों का प्रतिरोध शामिल है, जो इसे बेहतर पैदावार और लचीलापन चाहने वाले किसानों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाता है।
4. **गुजरात सरसों 7:** गुजरात में फसल जीन अन्वेषण और उपयोग की राज्य प्रमुख प्रयोगशाला द्वारा विकसित, बनास अनमोल सरसों उद्योग में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। यह किस्म विविध जलवायु परिस्थितियों के लिए उत्कृष्ट अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करती है और बढ़ी हुई तेल सामग्री, रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर फसल अवधि प्रदान करती है, जिससे यह गुजरात और उसके बाहर के किसानों के लिए एक आशाजनक विकल्प बन जाती है।

किस्मों का कठोर परीक्षण और मूल्यांकन किया गया

सरसों की इन नई किस्मों के आने से किसानों को उनकी विशिष्ट कृषि आवश्यकताओं और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यापक विकल्प उपलब्ध होने की उम्मीद है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गुणवत्ता मानकों, उत्पादकता क्षमता और उपयुक्तता के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए किस्मों का कठोर परीक्षण और मूल्यांकन किया गया है। केंद्रीय बीज समिति द्वारा इन भारतीय सरसों की किस्मों को मंजूरी देना कृषि नवाचार को बढ़ावा देने, फसल उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आनुवंशिक विविधता और उन्नत सरसों की किस्मों की उपलब्धता का विस्तार करके, सरकार का लक्ष्य किसानों को उच्च पैदावार, बेहतर फसल गुणवत्ता और बढ़ी हुई लाभप्रदता प्राप्त करने में सहायता करना है।

भारत में बासमती चावल की 45 अधिसूचित किस्में

भारत में बासमती चावल की 45 अधिसूचित किस्में

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

भारत में सदियों से, बासमती की खेती उपमहाद्वीप के हिमालय की तलहटी में की जाती रही है, जिससे चावल की एक किस्म तैयार होती है जो अपने असाधारण गुणों के लिए प्रसिद्ध है। अपने लंबे, पतले दानों के साथ नरम और फूली हुई बनावट, मनमोहक स्वाद, बेहतर सुगंध और विशिष्ट स्वाद के साथ, बासमती चावल अन्य सुगंधित लंबे दाने वाली किस्मों से अलग है। बासमती चावल की विशिष्ट विशेषताओं का श्रेय इसके विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के साथ-साथ कटाई, प्रसंस्करण और सावधानीपूर्वक विधियों को दिया जा सकता है। ये कारक मिलकर एक ऐसा चावल बनाते हैं जो वास्तव में अद्वितीय है और किसी भी भोजन में लालित्य का स्पर्श जोड़ता है, यहां तक कि सबसे सरल व्यंजन को भी स्वादिष्ट व्यंजन में बदल देता है।

खेती के क्षेत्र और बासमती चावल निर्यात में भारत का प्रभुत्व- भारत में बासमती चावल का उत्पादन मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों में होता है। भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल के प्रमुख निर्यातक के रूप में प्रमुख स्थान रखता है। अकेले वर्ष 2022-23 में देश ने 38,524.11 करोड़ रुपये (या 4,787.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य का 4,558,972.23 मीट्रिक टन बासमती चावल का प्रभावशाली निर्यात किया। इसी अवधि के दौरान, भारतीय बासमती चावल के उल्लेखनीय निर्यात स्थलों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और यमन गणराज्य शामिल थे। यह कई देशों में भारत के बेहतरीन बासमती चावल की व्यापक लोकप्रियता और मांग को उजागर करता है।

एक नजर भारत में अधिसूचित किस्मों पर

अब तक बासमती चावल की 45 किस्मों को बीज अधिनियम, 1966 के तहत अधिसूचित किया गया है। ये हैं बासमती 217, पंजाब बासमती 1 (बौनी बासमती), बासमती 386, पंजाब बासमती 2, पंजाब बासमती 3, बासमती 370, हरियाणा बासमती 1, तरौरी बासमती (एचबीसी 19), टाइप 3 (देहरादूनी बासमती), पंत बासमती 1 (आईईटी 21665), पंत बासमती 2 (आईईटी 21953), कस्तूरी, माही सुगंधा, बासमती सीएसआर 30 (संशोधन के बाद), मालवीय बासमती धान 10-9 (आईईटी 21669)), रणबीर बासमती, बासमती 564, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121 (संशोधन के बाद), पूसा बासमती 1509 (आईईटी 21960), पूसा बासमती 6 (पूसा 1401), पूसा बासमती 1609, पूसा बासमती 1637, पूसा बासमती 1728, वल्लभ बासमती 22, वल्लभ बासमती 21 (आईईटी 19493), वल्लभ बासमती 23, वल्लभ बासमती 24, पूसा बासमती 1718, पंजाब बासमती 4, पंजाब बासमती 5, हरियाणा बासमती 2, पूसा बासमती 1692, जम्मू बासमती 118, जम्मू बासमती 138, जम्मू बासमती 129, जम्मू बासमती 123, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 1985, पूसा बासमती 1979, पूसा बासमती 1882, पंजाब बासमती 7।

400 बीघा से अधिक फसल जलकर खाक, किसानों की बढ़ी चिंता

श्योपुर में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग

श्योपुर। जिले के सोंईकलां-गोपालपुरा क्षेत्र में खेतों में पककर तैयार खड़ी गेहूं की फसल भीषण आग में जलकर खाक हो गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। अज्ञात कारणों से भड़की आग पर जब तक काबू पाया जा सका तब तक आधा सैंकड़ा से ज्यादा किसानों की सालभर की मेहनत धुआं-धुआं हो गई। फायर बिग्रेड डेढ़ घंटे बाद मौके पर पहुंची, तब जाकर आग को बुझाया। इस आगजनी की घटना में 400 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधीश लोकेश कुमार जांगिड़ मौके पर पहुंचे जिन्होंने किसानों से चर्चा कर नुकसान के बारे में जानकारी ली। साथ ही कहा कि सर्वे के बाद नुकसान का किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

दमोह के तीन गांव में शॉर्ट सर्किट से फसल जली

इधर, दमोह के जबेरा ब्लॉक में आने वाले तीन गांवों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कई किसानों की फसल जलकर खाक हो गई। इसमें उनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। जबेरा तहसील के सिंगपुर, भाट खमरिया, सिमरी जालम गांव में यह हादसा हुआ। सिमरी जालम बस्ती के समीप खेत के ऊपर से निकली बिजली लाइन में तेज हवाओं के चलने से बिजली के तार आपस में टकराए। स्पार्किंग से निकली चिंगारी से खेत में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसानों के प्रयासों के बाद भी कई किसानों की फसल आग की चपेट में आ गई और जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने के लिए सामूहिक रूप से ग्रामीणों ने प्रयास किया। इसके बाद तेंदूखेड़ा एवं दमोह से दमकल वाहन ने आकर आग पर पूरी तरह से काबू पाया।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)